

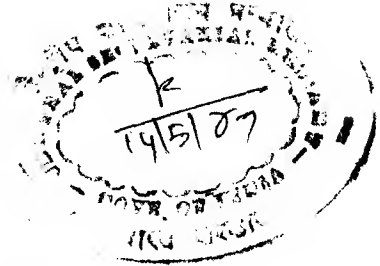


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



स. 53]
No. 53]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 1987/फाल्गुन 22, 1908
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 1987/PHALGUNA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1987

संकल्प

स. एफ. 14(2)/आई. सी./86.—केन्द्रीय सरकार के समूह "ख", "ग" और "घ" के सिविल कर्मचारियों से संबंधित चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में भारत सरकार के निर्णय, वित्त मंत्रालय के संकल्प संख्या 14(1)/आई. सी./86, दिनांक 13-9-1986 के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिए गए थे। सरकार ने अब, केन्द्रीय समूह "क" सेवाओं/पदों और साथ ही अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में परिलब्धियों, भत्तों और सेवा शर्तों के बारे में आयोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और यह निर्णय किया है कि इनके संबंध में आयोग की सिफारिशों को, निम्नलिखित संशोधनों के साथ, सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाए :—

I—अखिल भारतीय सेवाओं के वेतनमान :

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा :

भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ समय वेतनमान और प्रवरण ग्रेड क्रमशः 3200—4700 रुपये और 4800—5700 रुपये होगा तथा इस सेवा के लिए एक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (3050—5000 रुपये) (गैर-कार्यात्मक) होगा।

(ii) भारतीय पुलिस सेवा :

भारतीय पुलिस सेवा में एक गैर-कार्यात्मक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (3700—5000 रुपये) तथा प्रवरण ग्रेड (4500—5700 रुपये) होगा। पुलिस उप-महानिरीक्षक का वेतनमान 5100-150-5400-150-6150 रुपये (18वें वर्ष में अथवा उसके बाद 5400 रुपये) होगा। राज्यों में महानिदेशक (पुलिस) का वेतनमान 7300-100-7600 रुपये होगा बड़े राज्यों में 7600-100-8000 रुपये का वेतनमान होगा।

(iii) भारतीय वन सेवा :

भारतीय वन सेवा में 3700—5000 रुपये का एक गैर-कार्यरमक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, और 4100—5300 रुपये का एक प्रवरण ग्रेड होगा। वन संरक्षक का वेतनमान 4500—5700 रुपये होगा। अपर मुख्य संरक्षक और मुख्य संरक्षक का वेतनमान 5900—6700 रुपये होगा। प्रधान मुख्य संरक्षक का वेतनमान 7300—100-7600 रुपये होगा; बड़े राज्यों में वेतनमान 7600 रुपये (स्थिर) होगा।

II—केन्द्रीय समूह “क” सेवाओं/पदों के वेतनमान :

(i) जिन वैज्ञानिक संगठनों में लचीली अनुपूर्ति (फ्लेक्सिबल कम्पलीमेंटिंग) की स्कीम लागू है, उनमें वैज्ञानिक पदों पर लागू होने वाले वेतनमानों में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं :—

वर्तमान वेतनमान	आयोग द्वारा सिफारिश किया गया वेतनमान	संशोधित वेतनमान
रु.	रु.	रु.
1800—2250	4100—5300	4500—5700
2000—2500	4500—5700	5100—6300
2250—2750	5100—6700	5900—6700

(ii) महाविदेशक, श्री. एस. एफ. और महाविदेशक, श्री. आर. पी. एफ. के पद का वेतनमान 7600 रुपये (स्थिर) की बजाए जैसा कि आयोग ने सिफारिश किया है, 8000 रुपये (स्थिर) होगा।

(iii) भारत सरकार के अपर सचिव के पद व समकक्ष पदों का वेतनमान 7300-100-7600 रुपये होगा।

(iv) भारतीय विदेश सेवा का वरिष्ठ समय वेतनमान और प्रवरण ग्रेड क्रमशः 3200—4700 रुपये और 4800—5700 रुपये होगा और इस सेवा के लिए एक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (3950—5000 रुपये) (गैर-कार्यरमक) होगा।

III—अन्य मामलों से संबंधित सिफारिशें :

(i) यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक वेतन वृद्धि की योजना का, जिसकी अवधि ने सिफारिश की है, उन समूह “क” अधिकारियों पर लागू कर दिया जाए जिनका अधिकतम वेतनमान संशोधित वेतनमान में 6700 रुपये से अधिक नहीं है।

(ii) यह भी निर्णय किया गया है कि सी. एच. एस. में सामान्य इयूटी डाक्टरों और रेलवे तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों में डाक्टरों के सेवा शर्तों और सेवा में प्रोन्नति के बारे में जांच करने के लिए एक अन्तर-विभागीय समिति गठित की जाए क्योंकि आयोग ने ऐसी जांच किए जाने की सिफारिश की है।

(iii) वेतन निर्धारण, भत्तों की स्वीकृति, प्रभावी होने की तारीख आदि से संबंधित आयोग की सिफारिशों को, समूह “ख”, “ग” और “घ” के कर्मचारियों के संबंध में स्वीकृत सुधारों को, जहाँ कहीं व्यवहार्य हो, केन्द्रीय समूह “क” सेवाओं/पदों और अखिल भारतीय सेवाओं पर लागू करने के बाद, सामान्यतः दायरे में लाया जाएगा।

2 स्कीमिकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार यह आशा करती है कि समूह “क” और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, उपरोक्त निर्णयों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली, मार्च, 1986 के बाद की अवधि की बकाया राशि को भी अपनी भविष्य निधि में स्वेच्छापूर्वक विशेष तौर पर जमा करा देंगे। तथापि, सी. पी. एफ. में जमा की जाने वाली राशि के लिए, जिसमें जनवरी से मार्च, 1986 की अवधि भी शामिल है, सरकार से तदनुसूची अंशदान नहीं किया जाएगा।

3 इस संकल्प के साथ नयी विवरण के काखम 2 में वर्णित केन्द्रीय समूह “क” सेवाओं/पदों के संबंध में आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय विवरण के बाखम 3 में दर्शाया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में, उन निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए, जो भी उन पर लागू हों, इन सेवाओं के संबंध में नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

4 आयोग द्वारा की गई जो सिफारिशें अनुबंध में शामिल नहीं हैं, उन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और उनके संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों की अवधि से अधिसूचित कर दिया जाएगा।

अदेश

आदेश, दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के समाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, मध्य क्षेत्रों के प्रशासकों व अन्य सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

ए. संचाली, प्रधान सचिव

अनुबन्ध

समूह "क" सेवाओं/पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार द्वारा उन पर किए गए निर्णय बर्णन वाला विवरण।

(विवरण में अध्यायों और पैराग्राफों के बारे में जो संदर्भ दिए गए हैं वे वेतन आयोग की रिपोर्ट से संबंधित हैं)

क्र. सं.	चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें	सरकार द्वारा किया गया निर्णय
1	2	3
(1) वेतन		
(क) (i) समूह "क" सेवाओं/पदों के बारे में निम्नलिखित 15 संशोधित वेतनमान सुझाए गए हैं।		वैज्ञानिक पदों और अपर सचिव तथा उसके समकक्ष पदों पर लागू होने वाले कतिपय वेतनमानों में परिवर्तन करते हुए स्वीकृत। केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1986 में संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं।
1. 2200-75-2800-र.रो.-100-4000/- रु.		
2. 3000-100-3500-125-4500/- रु.		
3. 3000-100-3500-125-5000/- रु.		
4. 3700-125-4700-150-5000/- रु.		
5. 4100-125-4850-150-5300/- रु.		
6. 4500-150-5700/- रु.		
7. 5100-150-5700/- रु.		
8. 5900-200-6700/- रु.		
9. 5100-150-6300-200-6700/- रु.		
10. 5900-200-7300/- रु.		
11. 7300/- रु. निश्चित		
12. 7300-200-7500-250-8000/- रु.		
13. 7600/- रु. (निश्चित)		
14. 8000/- रु. (निश्चित)		
15. 9000/- रु. (निश्चित)		
(अध्याय 8, पैराग्राफ 8.9 तथा 8.73)		
(ii) जिन संशोधित वेतनमानों की सिफारिश अध्याय 8 में की गई है वे, उन पदों को छोड़कर स्वीकार कर ली गई।		
जिनके लिए विस्पष्ट रूप से अध्याय 9, 10, 11 और 27 में सिफारिशों की गई हैं, सभी पदों पर लागू होंगे। बहिष्कृत में सूचित किए जाने वाले किसी भी पद को आयोग की सिफारिश के अनुसार निर्धारित किसी भी एक या दूसरे वेतनमान में रख सकता संभव होना चाहिए।		
(अध्याय 8 पैराग्राफ 8.9 और 8.72)		
(iii) कतिपय पदों अथवा श्रेणियों के संशोधित वेतनमानों के संबंध में आयोग ने रिपोर्ट के अध्याय 9, 10, 11 और 27 में स्पष्ट सिफारिशों की हैं।		कतिपय संशोधनों के साथ स्वीकार कर ली गई है जिन्हें अलग से अधिसूचित किया जा रहा है। देशज औषध प्रणाली/ होम्योपैथी में डिग्रीधारियों के वेतनमानों के संबंध में आयोग की सिफारिशों के बारे में निर्णय बाद में घोषित किया जाएगा।
(अध्याय 10 पैराग्राफ 10.249)		
(iv) संशोधित केन्द्रीय सेवाओं में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड--II (2250--2500/- रु.) और स्तर--I (2500--2750/- रु.) के पदों को मिला दिया जाना चाहिए और उन्हें (5900-200-6700/- रु.) का वेतनमान दिया जाना चाहिए।		स्वीकार कर ली गई।
(अध्याय 8, पैराग्राफ 8.65)		
(ख) समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं के मामले में प्रवरण ग्रेड में पदोन्नति के लिए कमिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में अधिकतम दो वर्ष के गतिरोध की मौजूबा शर्त का हटा दिया जाना चाहिए।		स्वीकार कर ली गई।
प्रवरण ग्रेड में पदोन्नति के मानदण्ड और प्रवरण ग्रेड पदों की संख्या का हिसाब लगाने का प्राधार अखिल भारतीय और समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं में एक समान होना चाहिए।		
(अध्याय 23, पैराग्राफ 23.12)		

1	2	3
2.	जो व्यक्ति अपने वर्तमान के अधिकतम पर पट्टन जायें उन्हें राहत प्रदान करने के विचार से वरिष्ठ समय वर्तमान स्तर तक समूह "क" सेवाओं/पदों में सभी सेवाओं को संबद्ध वर्तमानों के अधिकतम वर्तमान पर हर दो वर्ष पूरा करने पर एक गतिरोध वर्तमानवृद्धि दी जाये। अधिक से अधिक ऐसी तीन वृद्धियां दी जा सकती हैं। (अध्याय 23, पैराग्राफ 23.10)	इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि गतिरोध वर्तमानवृद्धि की योजना समूह "क" के उन अधिकारियों पर लागू होगी जिनके वर्तमान का अधिकतम स्तर 6700/- रु. से अधिक न हो।
3.	पैराग्राफ 30.2 में वर्णित तरीके प्रस्तावित वर्तमान में कर्मचारियों का वेतन निश्चित किया जाये। (अध्याय 30)	इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि न्यूनतम लाभ 50/- रु. की बजाय 75/- रु. होना चाहिये।
4.	(1) वित्त नियम 22-ग एक पद से दूसरे पद पर पवोन्नति के सभी मामलों में लागू होना चाहिये बशर्ते कि उच्च पद में वेतन निर्धारित करने से पहले निम्न पद में जोड़ी जाने वाली राशि 25/- रु. से कम नहीं होनी चाहिये। (अध्याय 23, पैराग्राफ 23.14)	इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि कोई न्यूनतम लाभ की सीमा नहीं होगी।
(2)	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में प्रवर सचिव से उप-सचिव के पद पर पवोन्नति के मामले में न्यूनतम वृद्धि की राशि 150/- रु. से बढ़ाकर 250/- रु. कर दी जानी चाहिये। (अध्याय 9, पैराग्राफ 9.25)	प्रस्वीकृत। इन मामलों में भी वेतन का निर्धारण एक प्रार. 22 सी के अन्तर्गत किया जाना चाहिये जैसा कि अन्य पवोन्नतियों के मामलों में किया जाता है।
5.	मूल्य वृद्धि के लिये मुद्रावृद्धि	इस परिवर्तन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि मूल्य वृद्धि का मुद्रावृद्धि सितम्बर के वेतन के साथ पहली जुलाई से और मार्च के वेतन के साथ पहली जनवरी से प्रदा किया जायेगा।
(1)	जब तक सरकार किसी नये सूचक अंक का प्रतिस्थापित नहीं करती तब तक मूल्यवृद्धि के लिये कर्मचारियों को मुद्रावृद्धि दिये जाने के प्रयोजन से औद्योगिक कर्मचारी (सामान्य) अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (आधार 1960-100) को ही उपयोग में लाया जाना चाहिये।	
(2)	12 महीनों के सूचक अंको के 608 के औसत (1960=100), जिससे सिफारिशों के अनुसार निर्धारित वर्तमान संबंधित हैं, ऊपर मूल्य वृद्धि हो जाने पर मुद्रावृद्धि प्रदा किया जाना चाहिये।	
(3)	मुद्रावृद्धि की मंजूरी मार्च और सितम्बर के वेतनों के साथ प्रदा किये जाने के लिये एक वर्ष में दो बार प्रदान की जानी चाहिये।	टिप्पणी : वित्त मंत्रालय के का.जा. संख्या 13017/1/86-ई.-II(बी), दिनांक 24-6-86 के द्वारा 1-4-86 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते की जिन किस्तों की मंजूरी दी गई है और उसके अनुसरण में अप्रैल, मई और जून, 1986 में जिन धनराशियों की अदायगी कर दी गई है उनका संशोधित फार्मूले/वर्तमानों के संशोधन के कारण देय बढ़ाया राशि के अनुसार प्रदा किये जाने वाले महंगाई भत्ते में समायोजित कर दिया जायेगा।
(4)	उपयुक्त सूचक अंक के 12 महीनों के औसत में प्रत्येक वर्ष दिसम्बर और जून में समाप्त होने वाली अवधियों में 608 के औसत सूचक अंक से जितनी भी प्रतिशत वृद्धि हो उसे केवल संपूर्ण अंकों में ही ग्रहण किया जाना चाहिये और भिन्नात्मक वृद्धि को अग्रेशन कर देना चाहिये।	
(5)	मूल वेतन पर कर्मचारियों का प्रदेय मुद्रावृद्धि की दर, सूचक अंक के 608 अंक के औसत पर भी पूर्णों में परिकल्पित की जानी चाहिये और भिन्नात्मक वृद्धि को अग्रेशन किया जाना चाहिये।	
(6)	जो कर्मचारी 3500/- रु. तक का मूल वेतन ले रहे हैं, उनके लिये 100 प्रतिशत, 3501/- रु. से 6000/- रु. तक 75 प्रतिशत और 6000/- रु. से अधिक के लिये मामूली समायोजन करके 65 प्रतिशत मूल्यवृद्धि निराकरण की व्यवस्था की जानी चाहिये।	
(7)	मुद्रावृद्धि को परिवर्धियों के एक घनग तत्व के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिये। (अध्याय 13, पैराग्राफ 13.20)	
6.	विशेष वेतन	
	कुछ मामलों में आयोग ने संशोधित वर्तमानों की सिफारिश की है जिनमें विशेष वेतन भी सम्मिलित है। प्रस्तावित वर्तमानों को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश है कि विशेष वेतन की मौजूदा दरों को बहुत कहीं घटा हों, 500 रुपये प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत दृढ़ता कर दिया जाये।	स्वीकृत। संबंधित मंत्रालय/विभाग उन पदों की, जिनके लिये इस समय विशेष वेतन प्राप्ति है, ध्यान से समीक्षा करेंगे ताकि विशेष वेतन वाले पदों की संख्या को सीमित किया जा सके, तथा समीक्षा की परिणामों की रिपोर्ट कामिक और प्रशिक्षण विभाग के पास 31-5-1986 से पहले भेज देंगे।
7.	प्रतिनियुक्ति (इपूटी) भत्ता :	
	सरकार प्रस्तावित संशोधित वर्तमानों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति भत्ते का उपयुक्त रूप से निर्धारण कर सकती है। प्रतिनियुक्ति भत्ता एक निश्चित दर पर दिया जाना चाहिये, वेतन के प्रतिशत के रूप में नहीं। (अध्याय 24, पैराग्राफ 24.5)	प्रतिनियुक्ति (इपूटी) भत्ता एक ही शर्त में स्थानान्तरण के मामले में, 250 रुपये की उच्चतम सीमा के अधीन मूल वेतन के 5 प्रतिशत की दर से और अन्य मामलों में 500 रु. की उच्चतम सीमा के अधीन मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से दिया जायेगा।

1	2	3
---	---	---

8 प्रतिपूरक भत्ते : नगर पूरक भत्ता

- (i) शहरों की वहां की तुलनात्मक महंगाई के आधार पर वर्गीकृत करना बड़ा पेचीदा और कठिन कार्य है। इस मुद्दा का स्वीकार करना कठिन है कि नगरपूरक भत्ता सभी स्थानों पर दिया जाये क्योंकि सामान्य निर्वाह व्यय में होने वाली वृद्धि की प्रतिपूर्ति समय-समय पर महंगाई भत्ते की प्रदायगी की स्कीम द्वारा की जाती है।
(अध्याय 17, पैराग्राफ 17.3)

- (ii) प्रतिपूरक नगर भत्ता निम्नलिखित नीचे उल्लिखित निर्धारित दरों पर प्रदा किया जाये :-

वेतन रेंज	विभिन्न श्रेणी के नगरों में प्रति-पूरक नगर भत्ते की रकम (प्रति माह)			
	ए.	बी-1	बी-2	
2200 रुपये तथा उससे अधिक	100	75	20	स्वीकृत (कुछ विशेष स्थानों के मामले में, जहां पर यह भत्ता बी-2 श्रेणी शहरों पर लागू होने वाली दरों पर दिया जा रहा है, आवेश बलग से जारी किये जा रहे हैं)।

9. मकान किराया भत्ता :

- (i) नगरों की वर्तमान पर आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में मकान किराया भत्ता देने की मौजूदा प्रणाली को जारी रखा जाये।
(अध्याय 14, पैरा 14.25)
- (ii) नगरों की भी वर्तमान तीन श्रेणियों अर्थात् ख-I और ख-II तथा ग में वर्गीकृत किया जाना जारी रखा जाये। उन अवर्गीकृत शहरों/कस्बों में भी मकान किराया भत्ता प्रदा किये जाने की वास्तविक आवश्यकता है जहां इस समय यह देय नहीं है।
(अध्याय 14, पैराग्राफ 14.25)
- (iii) सरकारी कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते की प्रदायगी उस टाइप के सरकारी आवास के संदर्भ में की जानी चाहिये, जिसके लिये वे अपनी वेतन सीमा के आधार पर हकदार है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसी विशेष टाइप के आवास के हकदार, किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता निश्चित राशि में देय होना चाहिये और यह तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि उसकी हकदारी में परिवर्तन नहीं हो जाता।
(अध्याय 14, पैराग्राफ 14.26)
- (iv) कर्मचारियों का वर्गीकरण और विभिन्न श्रेणियों के शहरों में उन्हें देय मकान किराये भत्ते की राशि निम्नलिखित रूप में होनी चाहिये :-

जित टाइप के आवास के लिये हकदार है		हकदारी के लिये प्रस्तावित वेतनमानों में वेतन सीमा	निम्न श्रेणियों के शहरों में देय मकान किराये भत्ते की राशि		
			क, ख-I, और ख-II श्रेणी के शहर	ग श्रेणी के शहर	अवर्गीकृत स्थान
सी	2200-2799		450	220	100
डी	2800--3599		600	300	150
ई	3600--4499		800	400	200
ई-I	4500--6699	}	1000	500	300
ई-II	6700--7299				
ई-III	7300 और अधिक				

(अध्याय 14, पैराग्राफ 14.27)

1	2	3
(v) उक्त दरों पर मकान किराया भत्ता सभी कर्मचारियों को (उनको छोड़कर, जिन्हें सरकारी/किराये पर निवाश आवास प्रदान किया गया है) भत्ता दिया जाये, और इसके लिये उन्हें किराये को खर्च प्रस्तुत करना जरूरी नहीं होता चाहिये। लेकिन उनके लिये यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होना चाहिये कि वे किराये पर कुछ व्यय कर रहे हैं/किराये के संबंध में कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अपने स्वयं के मकानों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी उक्त दरों पर मकान किराया भत्ता दिया जाये, बशर्त कि वे यह प्रमाणपत्र दें कि वे मकान अथवा संपत्ति कर अथवा मकान के अनुसरण के संबंध में भ्रष्टाचारी/भ्रष्टाचार कर रहे हैं।		स्वीकृत
(अध्याय 14, पैराग्राफ 14.27)		
(vi) उन मामलों में, जहां कोई सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को किराये के बिना भ्रष्टाचार किया गया सरकारी आवास को जेवर करता है अथवा अपने माता-पिता, पुत्र-पुत्री, पत्नी अथवा पति को भ्रष्टाचार सरकारी आवास में रहना/रहती है, जो अन्य नहीं इस समय लागू है, वे लागू होती रहेंगी।		स्वीकृत
(अध्याय 14, पैराग्राफ 14.27)		
(vii) कुछ मामलों में वेतन की सीमा पर, जहां तक मकान किराया भत्ता दिया जाता है पाबंदियां लगी हुई हैं। उन सभी स्थानों पर, जहां इस समय वेतन के 15 प्रतिशत दर पर मकान किराया भत्ता देय है, वे उन दरों पर भत्ता दिया जाये, जिनकी सिफारिश वेतन आयोग द्वारा "क", "ख"-I और "ख"-II श्रेणी के नगरों के लिये की गई है। उन अन्य मामलों में, जिन पर विशेष प्रादेश लागू होते हैं, मकान किराया भत्ता उन दरों पर भत्ता दिया जाये, जिनकी सिफारिश वेतन आयोग ने "ग" श्रेणी के नगरों के लिये की है। इन दोनों मामलों में मकान किराया भत्ते के लिये वेतन की कोई उच्चतम सीमा नहीं होनी चाहिये।		स्वीकृत
(अध्याय 14, पैराग्राफ 14.28)		
(viii) जब तक सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, दमन और दीव में विशेष प्रादेशों के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता देना जारी रखती है, तब तक यह उस दर पर दिया जाये, जिनकी सिफारिश वेतन आयोग द्वारा "ग" श्रेणी के नगरों के लिये की गई है।		स्वीकृत
(अध्याय 14, पैराग्राफ 14.29)		
10. पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता/मानकालीन भत्ता :		
उन सभी स्थानों पर, जहां इस समय पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता देय है, समूचे वर्ष भर वर्तमान पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ते और मानकालीन भत्ते को मिलाकर एक संयुक्त भत्ता दिया जाए, जिसकी दरें निम्नलिखित हैं:—		स्वीकृत
वृत्तिप्राप्ति वेतन	संयुक्त पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ते की मासिक दर (रुपये)	
2200 रुपये और अधिक (अध्याय 17, पैराग्राफ 17.8)	150 रुपये	
11. प्रतिकूल जलवायु भत्ता :		
प्रतिकूल जलवायु भत्ता सरकारी कर्मचारियों को खराब जलवायु वाले क्षेत्रों में सेवा संबंधी कठिनाइयों के मुआवजे के रूप में दिया जाता है। यह भत्ता उन स्थानों पर दिया जाता है, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को भत्ता देने के लिए प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र घोषित किया गया हो। प्रतिकूल जलवायु भत्ता मौजूदा मानदंडों के आधार पर, लेकिन वेतन की किसी उच्चतम सीमा के बिना, इन निम्नलिखित दरों पर दिया जाना चाहिये:—		स्वीकृत
वेतन सीमा	प्रतिकूल जलवायु भत्ते की मासिक दर (रुपये)	
वृत्तिप्राप्ति वेतन 2200-2999 रु०	80	
वृत्तिप्राप्ति वेतन 3000 रुपये और अधिक (अध्याय 17, पैराग्राफ 17.14)	100	

(1)

(2)

(3)

12. परियोजना/निर्माण भत्ता :

केन्द्रिय सरकार के उन कर्मचारियों को जो बृहद परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में अविवक्षित और एकांत स्थानों पर काम कर रहे हों, परियोजना/निर्माण भत्ता दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्हें परियोजना स्थल पर आवास, स्कूलों, मार्केट, औषधालयों जैसी सुविधाओं के अभाव के लिए मुआवजा देना है। जब ये सुविधाएं परियोजना स्थल पर अथवा उसके निकट उपलब्ध हो जाती हैं, तो यह भत्ता चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाता है। वर्ष 1970 से शुरू होने वाले दशक में सरकार ने परियोजना भत्ता देने के मार्गदर्शक निर्देशों और उसकी स्वीकृति देने की प्रक्रिया को दोषरहित बनाया था। इसके बाद परियोजना भत्ता परियोजना-क्षेत्रों में परियोजना भिन्न कर्मचारियों को दिया जाने लगा, जिसकी दर परियोजना कर्मचारियों को देय भत्ते की दरों की 50 प्रतिशत थी। परियोजना भत्ते की अदायगी का विनियमन करने वाले मौजूदा निर्देशों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी दरों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाए:—

स्वीकृत

वेतन सीमा

परियोजना भत्ते की मासिक दरें (रुपये)

बुनियादी वेतन 2200-2999 रुपये

300

बुनियादी वेतन 3000 रुपये और अधिक

375

(अध्याय 17, पैराग्राफ 17.17)

13. विशेष प्रतिपूरक भत्ता:

सीमा क्षेत्र भत्ते, दूरस्थ स्थान भत्ते और कठिना क्षेत्र भत्ते के रूप में दिए जाने वाले विशेष प्रतिपूरक भत्ते की दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि मोटे रूप से एक ही प्रकार की स्थानीय कठिनाइयों, स्थितियों आदि वाले स्थानों के मामले में उनमें कुछ एक रूपता लाई जा सके। द्वितीय क्षेत्रों के मामले में दो विभिन्न किस्मों के भत्तों के स्थान पर एक ही संयुक्त प्रतिपूरक भत्ता देना वांछनीय होगा। इसके अलावा, ये भत्ते एक समान दरों पर दिये जाने चाहिए। सफाई किये गए वेतनमानों को ध्यान में रखते हुए, ये भत्ते निम्नलिखित दरों पर दिए जाएंगे:—

स्वीकृत

क्रम संख्या क्षेत्र विशेष प्रतिपूरक भत्ते की मासिक दरें (रुपये)

बुनियादी वेतन 2200-2999 रुपए बुनियादी वेतन 3000 रुपये और अधिक

1	2	3
1. पैरा 17.9 में दी गई सारणी की क्रम संख्या 1 से 10 में सूच्यबद्ध क्षेत्र	500	650
2. पैरा 17.9 में दी गई सारणी की क्रम संख्या 11 से 17 में सूच्यबद्ध क्षेत्र	400	525
3. पैरा 17.9 में दी गई सारणी की क्रम संख्या 18 से 24 में सूच्यबद्ध क्षेत्र	300	375
4. पैरा 17.9 में दी गई सारणी की क्रम संख्या 25 और 26 में सूच्यबद्ध क्षेत्र]	80	100

(अध्याय 17, पैराग्राफ 17.11)

14. मिजोरम में गड़बड़ वाला क्षेत्र भत्ता स्वीकृत।

सरकार, इराण द्वारा सुझाई गई विशेष प्रतिपूरक भत्ते की संशोधित दरों को ध्यान में रखते हुए मिजोरम में गड़बड़ वाला क्षेत्र भत्ता को जारी रखने की आवश्यकता को ज्ञात करे।

इसे रीच भत्ता विभाग की दरों पर दिया जाना रहे।

(अध्याय 17, पैरा 17.12)

(1)

(2)

(3)

15. जनजातीय क्षेत्र भत्ता

कुछ स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जनजातीय क्षेत्र भत्ता, संबन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले ऐसे ही भत्ते के आधार पर स्वीकृत किया गया है। लेकिन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते की दरें भिन्न हैं जो 20 रुपये से 50 रुपये मासिक तक हैं। इस भत्ते की दरें बढ़ी होनी चाहिए जिनको सिफारिश प्रतिकूल जलवायु भत्ते के लिए की गई है। हाल में कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को कुछ स्थानों पर जनजातीय क्षेत्र भत्ता स्वीकृत किया गया है, लेकिन इन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए इसकी मंजूरी नहीं दी गई है। यह भत्ता जनजातीय क्षेत्रों में तैनाती के लिए एक प्रोत्साहन स्वरूप इसकी मंजूरी राज्य सरकारों द्वारा की गई है, वहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी यह भत्ता दिया जाए।

स्वीकृत

(अध्याय 17, पैरा 17.15 और 17.16)

16. जोखिम भत्ता :

कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के जोखिम भत्ते को यक्तिसंगत बनाने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। मामले की सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाने वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जा सकती है। समिति न केवल कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए भत्ता मंजूर करने की आवश्यकता के बारे में जांच करे बल्कि इसकी पर्याप्तता की भी जांच करे। इसी दौरान, विद्यमान वर्गों में 100 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की जाती है।

विशेषज्ञ समिति नियुक्त किए जाने की सिफारिश स्वीकृत।
इसी बीच मौजूदा दरों पर जोखिम भत्ता देना जारी रखा जाए।

(अध्याय 17, पैरा 17.21 से 17.23)

17. यात्रा भत्ता

- (1) आयोग ने निपोट के अध्याय 18 में वर्णित यात्रा भत्ते से संबन्धित निम्नलिखित मामलों के संबन्ध में कुछ दरों और यात्रों के बारे में सिफारिश की है :—
- (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वर्गीकरण
- (ख) सड़क मील भत्ता।
- (ग) यात्रा और स्थानान्तरण पर रेल द्वारा यात्रा की हकदारी।
- (घ) दैनिक भत्ते की दर।
- (ङ) स्थानान्तरण अनुदान तथा पैकिंग भत्ता।
- (च) रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच व्यक्तिगत वस्तुओं का परिवहन।
- (छ) रेल द्वारा न जुड़े स्थानों के बीच वस्तुओं का परिवहन।
- (ज) स्थानान्तरण पर सरकारी कर्मचारियों का हकदारी
- (झ) वक्तों के लिए यात्रा महायान।
- (ञ) आश्रित संबंधियों के लिए आय की सीमा।

स्वीकृत

- (2) वायुयान से यात्रा करने के संबन्ध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि भारत सरकार के अवर सचिव तथा उसके समकक्ष अधिकारियों को देश से एंज्रोक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने को अनुमति प्रदान की जाए।

स्वीकृत

(3) सामान्य :

यात्रा अर्पेक्षित भत्ते की दरों की सरकार द्वारा समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और आवश्यक होने पर उन्हें संशोधित किया जाए।

स्वीकृत

(अध्याय 18, पैरा 18.17)

(1)

(2)

(3)

18. सवारी भत्ता

सवारी भत्ते की दूरे निम्न प्रकार संशोधित की जानी चाहिए :

सरकारी झूटी पर औसत मासिक यात्रा	भत्ता मोटरकार द्वारा	सवारी के अन्य वाहन द्वारा
	यात्रा के लिए सवारी भत्ते की दर	
201-300 कि.मी.	300 रुपये प्र.मा.	100 रुपये प्र.मा.
301-450 कि.मी.	450 रुपये प्र.मा.	130 रुपये प्र.मा.
451-600 कि.मी.	550 रुपये प्र.मा.	170 रुपये प्र.मा.
601-800 कि.मी.	650 रुपये प्र.मा.	200 रुपये प्र.मा.
800 कि.मी. से अधिक	800 रुपये प्र.मा.	230 रुपये प्र.मा.

सवारी भत्ते की अवधारणा के लिए अन्य बातें लागू रहेंगी।

(अध्याय 18, पैरा 18.6)

19. छुट्टी की हकदारी :

(i) यह सिफारिश की जाती है कि अर्जित अवकाश जमा होने की 180 दिन की विद्यमान सीमा को बढ़ाकर 240 दिन कर दिया जाए। यह भी सिफारिश की जाती है कि सेवा-निवृत्ति के समय अर्जित अवकाश के बदले तकद राजी की सीमा को भी बढ़ाकर 240 दिन कर दिया जाए।

स्वीकृत। सभी अधिकारियों को अवगत में अनुदेश जारी किए जाएंगे कि किसी भी कर्मचारी का, अपवाद से छुट्टी देने से इस्कार नहीं किया जाएगा।

(ii) इस समय अध्ययन संबंधी छुट्टी की मंजूरी की शर्त के अंतर्गत किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसी छुट्टी लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि वह सेवा-निवृत्त होने वाला है अथवा उसे उस तारीख से तीन वर्ष के अंदर सरकारी सेवा में सेवा-निवृत्त होने का विकल्प प्राप्त है, जिम तारीख को छुट्टी समाप्त होने के बाद उसके झूटी पर वापस आने की सम्भावना है। "अथवा सेवा-निवृत्त होने का विकल्प प्राप्त है" शब्दों को नियमों में निकाल दिया जाए। विद्यमान नियम स्पष्ट नहीं है कि क्या उन मामलों में भी अध्ययन छुट्टी मंजूर की जा सकती जिनमें अध्ययन संबंधी पाठ्यक्रम एक से अधिक अवधि में पूरा किया जाए। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए नियमों को संशोधित किया जाए और अध्ययन छुट्टी को, विद्यमान सीमाओं के अन्तर्गत जहाँ कहीं आवश्यक हों, दो अवधियों में लेने की अनुमति दी जाए।

स्वीकृत। केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 में आवश्यक संशोधन जारी कर दिए गए हैं।

(iii) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई को 15-15 दिन की दो किस्मों में अर्जित अवकाश जमा करने की मौजूदा प्रवृत्ति पर पुनर्विचार किया जाए ताकि जिन मामलों में कर्मचारियों ने पहली जनवरी अथवा पहली जुलाई को पहले ही 180 दिन का अर्जित अवकाश जमा कर लिया हो उन्हें छोटे वाले नुकसान को दूर किया जा सके।
(अध्याय 26, पैराग्राफ 26.2)

स्वीकृत। क्योंकि इससे उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनके पास पहली जनवरी अथवा पहली जुलाई से पहले कोई छुट्टी जमा नहीं होगी।

20. चिकित्सा सुविधाएं :

(क) जो कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें बहिरंग उपाज के लिए 25 रुपए प्रतिमाह के डिग्राब से निश्चित चिकित्सा भत्ता दे दिया जाए। किन्तु कैसर, मधुमेह आदि जैसी विशेष बीमारियों पर, जिनका रिपोर्ट के पैराग्राफ 16.9 में वर्णित किया गया है और अस्पताल में भर्ती होने पर किए जाने वाले खर्चों की, पहले की भांति सभी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की जाती रहेगी।
(अध्याय 16 पैराग्राफ, 16.9)

स्वीकृत। आवश्यकता पहले पर मम्बित दवाज की सुविधा प्रदान करने पर महत्व दिया गया है। त कि बिना आवश्यकता के भत्तों का भुगतान करने पर। मौजूदा कमियों को दूर करने और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है। इस बीच प्रतिपूर्ति योजना जारी रहेगी।

(ख) माता-पिता, बहनों, विधवा बहनों, नाबालिग भाइयों, तथा बच्चों की सरकारी कर्मचारी पर आश्रित माना जा सकता है यदि वे उसके साथ रहते हों और यदि उनकी पेंशन तथा मुख्य एवं सेवा-निवृत्ति उपदान लाभों के बराबर पेंशन की राशि समेत सभी स्रोतों से आय 500/- रुपए प्रतिमाह से कम हो।

स्वीकार कर लिया गया है।

(अध्याय 16, पैराग्राफ 16.10)

(1)

(2)

(3)

21. कार्य घंटे :

सरकारी कर्मचारियों के कार्य के घंटों पर जो इस समय 37-1/2 प्रति सप्ताह है, सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जाए और उनमें उत्पादकता के स्तर को बनाए रखने तथा उसमें सुधार करने की दृष्टि से यथोचित वृद्धि कर दी जाए।

(अध्याय 26, पैराग्राफ 26. 8)

स्वीकृत : प्रत्येक कार्य दिवस में 1/2 घंटे की वृद्धि करके कार्य के घंटे प्रति सप्ताह 40 कर दिए जाएंगे।

22. ग्रेडों तथा पदों का वर्गीकरण :

वर्गीकरण की मौजूदा पद्धति को जारी रखा जाए और समूह "क" के लिए संशोधित वर्गीकरण को अन्तर्गत में सिविल पद आने चाहिए जिनके वर्तमान की अधिकतम सीमा 4000/-रुपए से कम न हो। जहाँ कहीं इस तरह के परिवर्तन हों जिनका उल्लेख पैराग्राफ 26. 50 में किया गया है तो उन पदों के मामले में विद्यमान वर्गीकरण को जारी रखा जाए। किन्तु सरकार चाहे तो आवश्यकता पड़ने पर ऐसे मामलों में वर्गीकरण में पुनर्विचार कर सकती है।

(अध्याय 26, पैराग्राफ 26. 52)

विद्यमान वर्गीकरण माकेतिक रूप से जारी रखा जाएगा।

23. सामान्य भविष्य निधि :

सभी कर्मचारियों के लिए अंशदान की मौजूदा दरों पर भविष्य निधि योजना को प्रतिबन्ध बनाए रखा जाए। भविष्य निधि खाते से किसी भी प्रयोजन के लिए कोई अधिम लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भविष्य निधि खाते से वापस न की जाने वाली निकासियों को भी सीमित कर दिया जाना चाहिए और केवल बच्चों की उच्च शिक्षा, स्वयं अथवा बच्चों के विवाह, कर्मचारी की बीमारी और मकान बनाने के लिए प्लाट खरीदने, अपने रहने के लिए मकान/बना बनाया प्लॉट खरीदने के लिए, जिसमें प्लाट की लागत भी शामिल है, रकम निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए। निकासियों की राशि की सीमा तथा पात्रता शर्त पहले की भांति ही रखी जाएं, सिवाय किसी मकान को खरीदने के लिए निकासी के संबंध में; जिन मामलों में निकासी वाली राशि और/अथवा सेवा की अवधि के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए।

(अध्याय 20, पैराग्राफ 20. 4)

अंशदान की मौजूदा दरों पर सामान्य भविष्य निधि योजना को जारी रखने की सिफारिश स्वीकृत। अधिम और निकासी के नियमों को कड़ा बनाए जाने के बारे में दी गई अन्य सिफारिश की जांच की जानी है।

24. वेतनवृद्धि :

यसी स्तरों पर किन्तु सेवा के सबसे बरिष्ठ स्तरों पर कार्यनिष्ठावन से संबद्ध वेतनवृद्धियां केवल उन्हीं को दी जानी चाहिए जो पूर्ण संतोषजनक ढंग से सेवा करें। इस प्रयोजन के लिए सेवा नियमों में संतोषजनक सेवा की परिभाषा शामिल की जाए। कार्य-निष्ठावन के मूल्यांकन के लिए एक उचित मानदण्ड तैयार किया जाए और अधिकारियों का एक समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष श्रेणी निर्धारित की जाए। जिस कर्मचारी का निरन्तर उत्कृष्ट कार्यनिष्ठावन रहे उसे सीमित संख्या में बगैर पेशान वाले मकदमा या दृगुनी दर पर वार्षिक वेतनवृद्धि दे दी जाए।

(अध्याय 7, पैराग्राफ 7. 60)

स्वीकार नहीं की गई।

क्योंकि वेतनवृद्धि को रोकना सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों, 1965 के अन्तर्गत एक दण्ड है। इसलिए वेतनवृद्धि को रोकने की प्रक्रिया बड़ी पेचीदा बन जाएगी और यदि वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली गई तो इसे क्रियान्वित करना प्रशासनिक रूप से कठिन होगा। वेतनवृद्धि की हर प्रकम पर समीक्षा करना, कार्यकुशलता के लिए भी सहायक सिद्ध नहीं होगा। वक्षतारोध अथवा पवोन्नति के समय इस प्रकार की समीक्षा करना बेहतर होगा।

25. आयोग ने कुछ उच्च स्तर के पदों से संबद्ध सेवाओं में संवर्गीकरण का सुझाव दिया है, जैसे:—गार्ड, ग्रा. ए. एम. में विस्तीय आयुक्त (रेलवे), केन्द्रीय मण्डल इंजीनियरी सेवा महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक, इंडियन मर्याद सविस्/इंडियन इस्पेक्शन सविस् में में संभरण तथा निपटान महानिदेशक, भारतीय सांख्यिकी सेवा में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के महानिदेशक, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) और भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय नगर शुल्क सेवा में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर जोड़ और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में अध्यक्ष तथा सचिव। (अध्याय 10, पैराग्राफ 10. 398, 10. 116, 10. 465, 10. 20, 10. 353, 10. 200)

स्वीकार नहीं की गई।

26. भविष्य भविष्य :

(क.) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, सामान्य ड्यूटी अधिकारी वर्गों में निमित्त स्तरों पर पर्याप्त संख्या में पदों का सृजन करके उसे उपयुक्त रूप से पुनर्गठित किया जाए ताकि उच्चश्रेणी के अधिकारियों को सेवा में तरक्की के संतोषजनक अवसर प्राप्त हो सकें।

(अध्याय 10, पैराग्राफ 10. 231)

इस सेवा के डाक्टरों के संख्या को आर. संशोधनीय पदोन्नति अवसरों की जांच करके केवल एक अन्तर्विभागीय समिति नियुक्त की जाएगी।

(1)

(2)

(3)

(ब) केन्द्रीय पुलिस संगठन में चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति की संभावनाओं में सुधार करना आवश्यक है। संबंधित विभाग को इन अधिकारियों की सेवा कालीन उन्नति के अवसरों की जल्दी से फिर से जांच करनी चाहिए और इस सेवा का इस प्रकार पुनर्गठन किया जाए ताकि इन्हें भी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के बराबर पदोन्नति के अवसर मिल सकें।

(अध्याय 10, पैराग्राफ 10.259)

(ग) रेलवे चिकित्सा सेवा में विशेषज्ञों का अलग से कोई संबंध नहीं है और स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त डाक्टर विशेषज्ञों के रूप में कार्य करते हैं। रेलवे चिकित्सा सेवा के वर्तमान संबंध में इस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं। इस सेवा का पुनर्गठन करना आवश्यक है ताकि जहाँ कहीं आवश्यक हो, विशेषज्ञों के पदों के सृजन सहित, विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त संख्या में पदों का निर्माण किया जा सके।

(अध्याय 10, पैराग्राफ 10.403)

27. प्रभावी बनाने की तारीख :

(i) सिफारिश किए गए वेतनमानों का लाभ वर्तमान तृतीय वर्ष के प्रारंभ से देना प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक होगा।

अनुबन्ध की मद 1(क) में दी गई सिफारिशों के संबंध में निर्णय 1 जनवरी, 1986 से लागू किया जाएगा। पहली जनवरी, 1986 से मार्च, 1986 तक की अवधि के संबंध में बकायों की निचल राशि कर्मचारी के जी. पी. एफ./सी. पी. एफ. खाते में जमा कर दी जाएगी। सी. पी. एफ. योजना के अन्तर्गत होने वाले कर्मचारियों के मामले में सरकार (नियोक्ता) की ओर से कोई तदनुकूपी अंशदान नहीं किया जाएगा।

(ii) अन्य मामलों से संबंधित सिफारिशों के बारे में सरकार को उन्हें किसी उपयुक्त तारीख से लागू करने के लिए, सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जिनमें प्रशासनिक तथा सेवा पद्धति संबंधी कार्य भी शामिल हैं, स्पष्ट निर्णय लेने होंगे।

संबंधित सरकारों आदेश में प्रभावी होने की तारीख का उल्लेख कर दिया जाएगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 13th March, 1987

RESOLUTION

No. F.14(2)/IC/86.—The decisions of the Government of India on the recommendations of the Fourth Central Pay Commission relating to civilian employees of the Central Government in Group 'B', 'C' and 'D' were notified in the Ministry of Finance Resolution No. 14(1)/IC/86 dated 13th September, 1986. Government have now given careful consideration to the recommendations of the Commission relating to structure of emoluments, allowances and conditions of service in respect of the Central Group 'A' services/posts, as also those in the All India Services, and have decided that the recommendations of the Commission in respect of these shall be accepted broadly, subject to the modifications mentioned below :

I. PAY SCALES OF ALL INDIA SERVICES :

(i) Indian Administrative Service :

The Senior Time Scale and Selection Grade of the Indian Administrative Service are to be Rs. 3200-4700 and Rs. 4800-5700 respectively and there is to be a Junior Administrative Grade (Rs. 3950-5000) (non-functional) for this service.

(ii) Indian Police Service :

The Indian Police Service is to have a non-functional Junior Administrative Grade (Rs. 3700-5000) and a Selection Grade (Rs. 4500-5700). The pay scale of DIG of Police will be Rs. 5100-150-5400-150-6150 (Rs. 5400 in the 18th year or later). The pay scale of DG (Police) in States is to be Rs. 7300-100-7600; in big States, the scale is to be Rs. 7600-100-8000.

(iii) Indian Forest Service :

The Indian Forest Service is to have a non-functional Junior Administrative Grade of Rs. 3700-5000, and a Selection Grade of Rs. 4100-5300. Conservator of Forests is to be in the scale of Rs. 4500-5700. The Additional Chief Conservator and Chief Conservator will be in the scale of Rs. 5900-6700. Principal Chief Conservator is to be in the scale of Rs. 7300-100-7600; in big States, the pay will be Rs. 7600 (fixed).

II. PAY SCALES OF CENTRAL GROUP 'A' SERVICES/POSTS :

- (i) The following improvements have been made in the scales applicable to scientific posts in scientific organisations in which the scheme of Flexible Complementing is applicable :

Existing Scale (Rs.)	Scale recommended by the Commission (Rs.)	Revised Scale (Rs.)
1800-2250	4100-5300	4500-5700
2000-2500	4500-5700	5100-6300
2250-2750	5100-6700	5900-6700

- (ii) The pay scale of the post of Director General, BSF and Director General, CRPF will be Rs. 8000 (fixed) instead of Rs. 7600 (fixed) as recommended by the Commission.
- (iii) Pay scale of post of Additional Secretary to Government of India and equivalent is to be Rs. 7300-100-7600.
- (iv) The Senior Time Scale and Selection Grade of the Indian Foreign Service are to be Rs. 3200-4700 and Rs. 4800-5700 respectively and there is to be a Junior Administrative Grade (Rs. 3950-5000) (non-functional) for this Service.

III. RECOMMENDATIONS RELATING TO OTHER MATTERS :

- (i) It has been decided to extend the scheme of stagnation increment, recommended by the Commission, Group 'A' officers maximum of whose pay scale does not exceed Rs. 6700 in the revised scale.
- (ii) It has also been decided to set up an inter-departmental Committee to look into the structure of services and career progression of General Duty Doctors in CHS and Doctors in Railways and Central Police Organisations as such an examination has been suggested by the Commission.
- (iii) The recommendations of the Commission relating to fixation of pay, grant of allowances, date of effect etc. shall be accepted broadly after extending, wherever applicable, to Central Group 'A' services/posts and the All India Services, the improvements which have been accepted in regard to the employees of Groups 'B', 'C' and 'D'.

2. In view of the need for containing inflationary trends Government hope that Group 'A' and All India Services officers will voluntarily make a special deposit of the arrears of pay on account of the above decisions for the period beyond March, 1986, also in their provident fund account. The deposits made in the CPF account including for the period January to March, 1986 will, however, not be eligible for corresponding contribution from Government.

3. The decisions of the Government on the recommendations of the Commission in respect of Central Group 'A' services/posts mentioned in Column 2 of the statement annexed to this Resolution are indicated in Column 3 thereof. In regard to the All India Services, appropriate action will be taken by the Cadre Controlling Authority of these services to give effect to the decisions as may be applicable to them.

4. The recommendations made by the Commission, which are not included in the Annexure, are being examined by the Government and decisions thereon will be notified separately.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of Union Territories and all others concerned.

A. RANGACHARI, Addl. Secy.

ANNEXURE

Statement showing the recommendations of the Fourth Central Pay Commission relating to employees in Group 'A' Services/Posts and Government's decision thereon. (References to Chapters and paragraphs in the statement are to the Pay Commission's Report).

Sl.No.	Recommendations of the Fourth Pay Commission	Decision of Government
1	2	3
1. PAY		
(a)	(i) The following 15 revised pay scales have been recommended for the Group 'A' Services/Posts.	Accepted subject to changes in certain scales applicable to scientific posts and posts of Additional Secretary and equivalent. Amendments to Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1986 are being issued separately.
	1. Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000	
	2. Rs. 3000-100-3500-125-4500	
	3. Rs. 3000-100-3500-125-5000	
	4. Rs. 3700-125-4700-150-5000	
	5. Rs. 4100-125-4850-150-5300	
	6. Rs. 4500-150-5700	
	7. Rs. 5100-150-5700	
	8. Rs. 5900-200-6700	
	9. Rs. 5100-150-6300-200-6700	
	10. Rs. 5900-200-7300	
	11. Rs. 7300/- (fixed)	
	12. Rs. 7300-200-7500-250-8000	
	13. Rs. 7600/- (fixed)	
	14. Rs. 8000/- (fixed)	
	15. Rs. 9000/- (fixed)	
	(Chapter 8, paragraphs 8.9 and 8.73)	
	(ii) The revised pay scales recommended in Chapter 8, shall apply to all posts other than those for which specific recommendations have been made in Chapters 9, 10, 11 and 27. It should be possible to place any post created in future in one or the other scales recommended by the Commission.	Accepted
	(Chapter 8, paragraphs 8.9 and 8.72)	
	(iii) Specific recommendations have been made in Chapters 9, 10, 11 and 27 in regard to revised scales of certain posts or categories. (Chapter 10)	Accepted subject to certain modifications which are being notified separately. Decision on the Commission's recommendations on the pay scales for degree holders in indigenous System of Medicine/Homocopathy will be announced later.
	(iv) The posts in the Senior Administrative Grade Level-II (Rs. 2250-2500) and Level-I (Rs. 2500-2750) in the organised Central Services should be merged and given the scale of Rs. 5900-200-6700. (Chapter 8, paragraph 8.65)	Accepted.

1

2

3

- (b) In respect of Group 'A' Central Services, the present condition regarding stagnation at the maximum of the Junior Administrative Grade for two years for promotion to the Selection Grade, should be removed. The criteria for promotion to the Selection Grade and the basis for computing the number of Selection Grade posts should be uniform in All India and Group 'A' Central Services.

Accepted.

(Chapter 23, paragraph 23.12)

2. In order to provide relief to those who reach the maximum of their pay scale, one stagnation increment on completion of every two years at the maximum of the respective scales may be granted to all cadres in Group 'A' Services/Posts upto the Senior Time Scale Level. A maximum of three such increments may be allowed.

(Chapter 23, paragraph 23.10)

Accepted with the modification that the scheme of stagnation increment will apply to Group 'A' officers maximum of whose scale does not exceed Rs. 6700/-.

3. The pay of employees may be fixed in the proposed scales of pay in the manner laid down in paragraph 30.2.

(Chapter 30)

Accepted subject to the modification that the minimum benefit shall be Rs. 75/- instead of Rs. 50/-.

4. (i) FR-22.C should apply to all cases of promotion from one post to another subject to the condition that the amount to be added to pay in the lower post before fixing the pay in the higher post should not be less than Rs. 25/-.

(Chapter 23, paragraph 23.15)

Accepted subject to the modification that there shall be no minimum benefit.

- (ii) The amount of the minimum increase in the case of promotion from Under Secretary to Deputy Secretary in the Central Secretariat Service may be raised from Rs. 150/- to Rs. 250/-.

(Chapter 9, paragraph 9.25)

Not accepted. In these cases also pay should be fixed under FR-22C as in all over promotions.

5. COMPENSATION FOR PRICE RISE

- (i) Till a new index is approved by Government, the All India Average Consumer Price Index numbers for Industrial Workers (General) (Base 1960=100) may continue to be used for grant of compensation to employees for price rise.

- (ii) Compensation may be paid for the price increase above the 12 monthly index average of 608 (1960=100) to which the pay scales recommended are related.

- (iii) Compensation may be sanctioned twice a year payable with the salary for March and September.

- (iv) The percentage increase in the 12 monthly average of the above index for the periods ending December and June each year over index average 608 may be taken in whole numbers only with fractions carried forward.

- (v) The rate of compensation to the employees over the basic pay at index average 608 may also be in whole numbers with fractions carried forward.

- (vi) Employees drawing basic pay upto Rs. 3500/- may be allowed 100% neutralisation, those between Rs. 3501/- to Rs. 6000/- be allowed 75% and those above Rs. 6000/- be allowed 65% subject to marginal adjustment.

- (vii) The compensation may continue to be shown as a distinct element of remuneration.

(Chapter 13, paragraph 13.20)

Accepted subject to the modification that compensation for price rise would be paid from 1st July with salary for September and from 1st January with salary for March.

Note :—The instalment of Additional Dearness Allowance sanctioned from 1-4-1986 vide Ministry of Finance O.M. No. 13017/1/86-E.II (B) of 24-6-1986 and amounts paid pursuant thereof for April, May and June 86 will be adjusted against the D.A. payable under the revised formula/arrears on account of revision of pay scales.

1	2	3
---	---	---

6. SPECIAL PAY :

The commission has suggested revised scales of pay inclusive of special pay in some cases. Keeping in view the scales of pay proposed, it is recommended that the existing rates of special pay, wherever admissible may be doubled subject to a ceiling of Rs. 500 per month.

Accepted. Ministries/Departments concerned will separately undertake review of posts for which special pay is now admissible with a view to limiting the number of special pay posts and report result of review to Department of Personnel & Training before 31-5-87.

7. DEPUTATION (DUTY) ALLOWANCE :

Government may suitably determine the rates of Deputation Allowance with reference to the revised pay scales proposed, Deputation Allowance may be given at fixed rates and not as a percentage of pay. (Chapter 24, paragraph 24.5)

Deputation (Duty) Allowance should be paid at the rate of 5% of basic pay subject to a ceiling of Rs. 250 for transfers within the same station and at the rate of 10% of basic pay subject to a ceiling of Rs. 500/- in other cases.

8. COMPENSATORY ALLOWANCE

City Compensatory Allowance :

- (i) Classifying cities on the basis of their comparative costliness is a complicated and time consuming process. The suggestion that CCA should be paid at all places is difficult to accept as increases in the general cost of living are compensated by the scheme of payment of dearness allowance from time to time.

Accepted.

(Chapter 17, paragraph 17.3)

- (ii) CCA may be paid at the fixed rates mentioned below :—

Pay range	Amount of CCA in class of cities (Rs. p.m.)		
	A	B-1	B-2
Rs. 2200 and above	100	75	20

(Chapter 17, paragraph 17.4)

Accepted (for special localities where CCA at the rates applicable to B-2 class city are being paid, fresh orders will be issued separately).

9. HOUSE RENT ALLOWANCE :

- (i) The existing system of payment of HRA with reference to classification of cities based on population may continue.

Accepted.

(Chapter 14, paragraph 14.25)

- (ii) The cities may also continue to be grouped into the existing three classes viz. A, B-1 and B-2 and C. There is a genuine need for payment of HRA in unclassified cities/towns also, where it is not admissible at present.

Accepted.

(Chapter 14, paragraph 14.25)

- (iii) The payment of HRA to Government employees should be related to the type of Government accommodation to which they are entitled on the basis of pay ranges. Under this arrangement fixed amount of HRA should be admissible to an employee entitled to a particular type of accommodation and this would not change until there is a change in his entitlement.

Accepted.

(Chapter 14, paragraph 14.26)

1

2

3

- (iv) The groupings of employees and the amount of HRA in different classes of cities may be as follows :—

Accepted.

Type of accommodation to which entitled	Pay range in proposed scale for entitlement (Rs.)	Amount of House Rent Allowance payable in		
		A, B-1 & B-2 class cities (Rs.)	'C' class cities (Rs.)	Unclassified places (Rs.)
1	2	3	4	5
C	2200–2799	450	220	100
D	2800–3599	600	300	150
E	3600–4499	800	400	200
E1	4500–6699	1000	500	300
E2	6700–7299			
E3	7300 and above			

(Chapter 14, paragraph 14.27)

- (v) HRA at the above rates may be paid to all employees (other than those provided Government owned/hired accommodation) without requiring them to produce rent receipts. They should, however, be required to furnish a certificate to the effect that they are incurring some expenditure on rent/contributing towards rent. HRA at the above rates may also be paid to Government employees living in their own houses subject to their furnishing a certificate that they are paying/contributing towards house or property tax or maintenance of the house.

Accepted.

(Chapter 14, paragraph 14.27)

- (vi) The other conditions at present applicable for the grant of HRA in cases where a Government employee shares Government accommodation allotted rent free to another Government employee or resides in Government accommodation allotted to his/her parents, son, daughter, wife or husband shall continue to be applicable.

Accepted.

(Chapter 14, paragraph 14.27)

- (vii) There are also restrictions in some cases on the limit of pay upto which HRA is given. In all places where HRA is presently admissible at 15 per cent of pay, the same may be paid at the rates mentioned at (iv) above for A, B-1 and B-2 class cities. In other cases covered by special orders, HRA may be paid at the rate mentioned at (iv) above for 'C' class cities. In both these cases there should be no upper pay limit for payment of HRA.

Accepted.

(Chapter 14, paragraph 14.28)

- (viii) So long as the Government continue to extend payment of HRA in the Union Territory of Goa, Daman and Diu under special orders, it may be paid at rate mentioned at (iv) above for 'C' class cities.

Accepted.

(Chapter 14, paragraph 14.29)

10. HILL COMPENSATORY ALLOWANCE/WINTER ALLOWANCE :

A composite allowance inclusive of the present HCA and WA should be allowed throughout the year at all places where HCA is presently admissible. The rates may be as follows :--

Accepted

Basic Pay Rs. 2200 and above	Rate of composite HCA per month Rs. 150/- (Chapter 17, paragraph 17.8)
---------------------------------	--

11. BAD CLIMATE ALLOWANCE :

Bad Climate Allowance (BCA) is granted to Central Government employees to compensate them for the rigours of service in areas which have a bad climate. The allowance is granted at those places which are declared by State Governments concerned as bad climate areas for grant of allowance to their staff. Payment of BCA on the existing criteria, without, however, any upper pay limit should be made at the following rates :-

Accepted

Pay range	Rate of Bad Climate Allowance per month (Rs.)
Basic pay Rs. 2200—2999	80
Basic Pay Rs. 3000/- and above.	100

(Chapter 17, paragraph 17.14)

12. PROJECT/CONSTRUCTION ALLOWANCE :

Central Government employees working at underdeveloped and out of the way places in connection with construction of major projects are granted a project/construction allowance, which is primarily intended to compensate them for lack of amenities such as housing, schools, market, dispensaries at the project sites. The allowance is withdrawn in a phased manner as and when these amenities become available at or near the project site. Guidelines for the grant of project allowance and the procedure for sanctioning the same were streamlined by the Government in mid seventies. The project allowance has also subsequently been extended to non-project employees located in project areas, at 50 per cent of the rates admissible to project employees. No change in the existing guidelines regulating grant of project allowance is necessary but the rates may be revised as follows :—

Accepted

Pay range	Rate of Project Allowance per month (Rs.)
Basic pay Rs. 2200-2999	300
Basic pay Rs. 3000/- and above	375

(Chapter 17, paragraph 17.17)

13. SPECIAL COMPENSATORY ALLOWANCE

There is need for rationalising the rates of Special Compensatory Allowance in the nature of border areas allowance, remote locality allowance and difficult areas allowance so as to bring about some uniformity in them for places with broadly similar local difficulties, conditions, etc. In the case of the Islands territories, it will be desirable to have one composite compensatory allowance, instead of two different types of allowances. Moreover, these allowances should be paid at

Accepted.

flat rates. Keeping in view the pay scales recommended, these allowances may be paid at the following rates :-

Sl. No.	Areas	Rates of Special Compensatory Allowance (Rs. p.m.)	
		Basic pay Rs. 2200-2999	Basic pay 3000/- and above
1.	Areas listed at Sl. Nos. 1 to 10 of the Table given at paragraph 17.9	500	650
2.	Areas listed at Sl. Nos. 11 to 17 of the Table given at paragraph 17.9	400	525
3.	Areas listed at Sl. Nos. 18 to 24 of the Table given at paragraph 17.9	300	375
4.	Areas listed at Sl. Nos. 25 and 26 of the Table given at paragraph 17.9	80	100

(Chapter 17, paragraph 17.11)

14. DISTURBED AREA ALLOWANCE IN MIZORAM

The need for continuance of Special Allowance (Disturbed Area Allowance) in Mizoram and rates thereof may be examined by Government taking into account the revised rates of specific compensatory allowances suggested by commission.

Accepted. Meanwhile the allowance may continue to be paid at the existing rates.

(Chapter 17, paragraph 17.12)

15. TRIBAL AREA ALLOWANCE

Tribal Area Allowance (TAA) has been granted to Central Govt. employees in a few places on the basis of grant of similar allowance by the respective State Governments to their employees. The rates of allowance for the Central Government employees are, however, different and range from Rs. 20/- to Rs. 50/- per month. The rates for this allowance should be the same as recommended for BCA. TAA has recently been sanctioned in a few places by some State Governments to their employees, but it has not been extended to Central Government employees in those areas. The TAA is intended as an incentive for posting in Tribal areas and it may be extended to Central Government employees in areas where it has been sanctioned by State Governments.

Accepted

(Chapter 17, paragraphs 17.15 & 17.16)

16. RISK ALLOWANCE

There have been suggestions for rationalising risk allowance to various categories of employees exposed to hazards. The matter may be examined by an Expert Committee to be appointed by Government for the purpose. The Committee should not only examine the need for grant of allowance for different categories of employees but also its adequacy. In the meantime, 100% increase in the existing rates is recommended.

The recommendation for appointing an Expert Committee is accepted. In the meantime, risk allowance may continue to be paid at the existing rates.

(Chapter 17, paragraphs 17.21 to 17.23)

1

2

3

17. TRAVELLING ALLOWANCE

(i) The Commission has made recommendations in respect of certain rates and/or conditions regarding the following matters in respect of travelling allowance contained in Chapter 18 of the report. Accepted.

- (a) Gradation of Central Government employees.
- (b) Road Mileage Allowance.
- (c) Entitlement for Journey by Rail on tour and transfer.
- (d) Rates of Daily Allowance.
- (e) Transfer Grant and Packing Allowance.
- (f) Transportation of personal effects between places connected by rail.
- (g) Transportation of goods between places not connected by rail.
- (h) Entitlement of Government employees on transfer.
- (i) Travel Assistance for children.
- (j) Income ceiling for dependent relatives.

(ii) No change appears to be called for in regard to travel by air except that Additional Secretary to Government of India and officers of equivalent rank may be allowed to travel by executive class while travelling by air within the country. Accepted.

(Chapter 18, paragraph 18.10)

(iii) GENERAL

Rates of the TA/DA may be reviewed by Government periodically and revised as and when necessary. Accepted.

(Chapter 18, paragraph 18.17)

18. CONVEYANCE ALLOWANCE

The rates of conveyance allowance should be revised as mentioned below : Accepted.

Average monthly travel on official duty	Rates of conveyance allowance for journeys by	
	Owmed Motor Car	Other modes of Conveyance
201-300 Km.	Rs. 300/- p.m.	Rs. 100/- p.m.
301-450 Km.	Rs. 450/- p.m.	Rs. 130/- p.m.
451-600 Km.	Rs. 550/- p.m.	Rs. 170/- p.m.
601-800 Km.	Rs. 650/- p.m.	Rs. 200/- p.m.
Above 800 Km.	Rs. 800/- p.m.	Rs. 230/- p.m.

Other conditions of drawal of conveyance allowance will continue to apply.

(Chapter 18, paragraph 18.6)

19. LEAVE ENTITLEMENTS

- (i) It is recommended that the existing limit of 180 days on accumulation of earned leave may be raised to 240 days. It is also recommended that the limit of encashment of Earned Leave at the time of retirement may also be raised to 240 days.
- Accepted. Instructions have been issued separately to all authorities to ensure that leave shall [not ordinarily be denied to any Govt. employee.
- (ii) At present the conditions for grant of study leave preclude a Government employee from availing of such leave if he is due to retire or has option to retire from Government service within three years of the date on which he is expected to return to duty after the expiry of leave. The words "or has the option to retire" may be deleted from the rules. The present rules are not clear whether study leave can be granted in cases where the course of study is completed in more than one spell. The rules may be modified to make the position clear and study leave may, subject to existing limits be permitted in two spells where necessary.
- Accepted. Necessary amendments to the Central Civil [Services (Leave) rules, 1972-1 have already been issued.
- (iii) The present procedure of crediting E.L. in two instalments of 15 days each on January and July 1st of every calendar year may be reviewed to remove disadvantages to employees in cases where they have already accumulated 180 days E.L. before January 1st or July 1st.
- Not accepted as it will adversely affect employees having no leave at their credit before January 1st or July 1st.

(Chapter 26, paragraph 26.2)

20. MEDICAL FACILITIES

- (a) For employees covered by medical reimbursement scheme a fixed medical allowance of Rs. 25/- per month for out door treatment may be paid. However, the expenses incurred on the special diseases like cancer, diabetes, etc. as detailed in paragraph 16.9 of the Report and hospitalisation may continue to be re-imbursed to all employees as at present.
- Not accepted. The emphasis is on providing adequate medical care where needed and not on disbursement of allowances irrespective of need. Separate action is being taken to eliminate the existing weaknesses and for extension of CGHS coverage. Meanwhile, the re-imburement scheme will continue.

(Chapter 16, paragraph 16.9)

- (b) Parents, sisters, widowed sisters, minor brothers and children may be deemed to be dependent on the Government employee if they are residing with him and if their incomes from all sources including pension and pension equivalent of DCRG benefits is less than Rs. 500/- p.m.
- Accepted.

(Chapter 16, paragraph 16.10)

1

2

3

21. HOURS OF WORK :

Working hours of office staff which are at present 37-1/2 hours a week may be reviewed by Government and increased suitably keeping in view the need to maintain and improve the level of productivity.

(Chapter 26, paragraph 26.6)

Accepted. The number of working hours shall be increased to 40 hours per week by adding 1/2 hour per working day.

22. CLASSIFICATION OF SERVICES AND POSTS :

The present system of classification may be continued and the revised classification for Group 'A' should be Central Civil post carrying a pay or scale of pay with a maximum of not less than Rs. 4000/-. Wherever there are deviations of the nature mentioned in paragraph 26.50 the existing classification for those posts may continue. Government may, however, review the classification in such cases as and when necessary.

(Chapter 26, paragraph 26.52)

Existing classification shall be continued notionally.

23. GENERAL PROVIDENT FUND :

Provident Fund scheme may continue to be compulsory for all employees at the existing rate of contribution. No advance shall be permitted from Provident Fund Account for any purpose whatsoever. Non-refundable withdrawals from the Provident Fund account should also be restricted and allowed only for purposes of higher education of children, marriage of self or children, illness of the employees and for purchasing a house site for building a house thereon, building/acquiring a house or a built flat for his residence including cost of the site. The limits and eligibility conditions for withdrawals may continue to be as at present except that in respect of withdrawal for owning a residence, there may be no restrictions on the amount to be withdrawn and/or the service rendered.

(Chapter 20, paragraph 20.4)

Recommendations to continue GPF Scheme at the existing rates of contribution accepted. The other recommendations to tighten rules for advance and withdrawals to be examined.

24. INCREMENT :

There should be a system of performance related pay at all but the most senior levels of service. The increments in scales of pay may thus be admissible only to those who give fully satisfactory service. For this purpose, the definition of satisfactory service may be provided in the Service Rule. A suitable criterion may be formulated for performance evaluation and rating may be made annually by a Committee of Officers; an employee who gives consistent excellent performance should be considered for a limited number of non-pensionable cash benefits or increment at double the rate.

Not accepted as withholding of an increment is a penalty under the CCS (CCA) Rules, 1963. The procedure, therefore, for withholding of an increment would become very cumbersome and if the recommendation of the

1

2

3

(Chapter 7, paragraph 7.60)

Pay Commission is accepted. It would be administratively difficult to implement. It will also not be conducive to efficiency that every stage of increment should be so reviewed. Such a review should better be done at the stage of crossing of Efficiency Bar or for promotion.

25. Encadrement of certain high level posts in the respective service has been suggested by the Commission for example, Financial Commissioner (Railways) in the IRAS, FA (Defence) in the IDAS, DG and Addl. DG, Roads in Central Engineering Service (Roads), DG Supplies & Disposal in Indian Supply Service/Indian Inspection Service, DG CSO in the Indian Statistical Service, Chairman and members of CBDT and CBEC in Indian Revenue service (Income Tax) and Indian Custom and Central Excise Service.

Not accepted.

(Chapter 10 Paragraphs 10.398, 10.416, 10.435, 10.28, 10.353 and 10.200)

26. MEDICAL OFFICERS :

- (a) Central Health Service, General Duty Officers Cadre, may be suitably structured by having adequate number of posts at different levels to provide satisfactory career progression to Officers of this category.

(Chapter 10, Paragraph 10.231)

An inter-departmental Committee will be set up to look into the structure and career progression of Services of these doctors.

- (b) It is necessary to improve the career prospects of Medical Officers in Central Police Organisations. The Department concerned should re-examine the career progression of these officers at an early date and so restructure the service that the officers may have the same prospects of promotion which are available to Medical Officers of the same grade in Central Health Service.

(Chapter 10, Paragraph 10.259)

- (c) Railway Medical Service has no separate Cadre of specialists and doctors possessing post graduate qualification work as specialists. The present cadre structure in RMS does not provide enough opportunities of promotion to Officers of this service. The service requires re-organisation with adequate number of posts at different levels, including creation of posts of specialists, wherever necessary. (Chapter 10, Paragraph 10.403)

27. DATE OF EFFECT :

- (i) It would be administratively convenient to give the benefit of the scale of pay recommended from the beginning of the current financial year.

(Chapter 31, Paragraph 31.2)

The decisions of the recommendations listed at item 1(a) of the Annexure shall be made applicable with

effect from 1st January, 1986. The net amount of arrear for the period January to March, 1986 will be deposited in the GPF/CPF Account of the employees. In the case of employees covered by CPF Scheme there will be no corresponding contribution from Government (Employer's) side.

- (ii) In regard to recommendations on other matters, Government will have to take specific decisions to give effect to them from a suitable date, keeping in view all relevant aspects, including the administrative and accounting work. Date of effect will be specified in the relevant orders.

(Chapter 31, Paragraph 31.2)

